'आर्मी डे परेड ने देशभक्ति व सैन्य गौरव की भावना को जन-जन तक पहुंचाया'

मुख्यमंत्री भजनलाल ने सेना दिवस परेड -2026 संकलन पुस्तक व लघु फिल्म का विमोचन किया

जयपुर, 06 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 78वें सेना दिवस पर आयोजित हुई ऐतिहासिक आर्मी डे परेड ने भारतीय सेना और जनमानस के बीच सेतु बांधने का काम किया तथा इस परेड ने राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और सैन्य गौरव की भावना को जन-जन तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार आर्मी डे परेड का छावनी क्षेत्र के बाहर आम नागरिकों के बीच जयपुर में सम्पन्न होना हम सब के लिए गौरव की बात है।

शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सेना दिवस परेड-2026 संकलन पुस्तक एवं लघु फिल्म के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी 2026 की तारीख राजस्थान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गई है। भव्य और व्यापक आर्मी डे परेड आयोजित कर हमने राजस्थान में नई परंपरा की शुरुआत की है।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जन भागीदारी ही किसी भी राष्ट्रीय उत्सव की असली शक्ति होती है। आर्मी डे परेड को आम लोगों ने अपने स्नेह और उत्साह से सफल बनाया।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 78वें सेना दिवस पर "आर्मी डे परेड संकलन" पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान सप्तशक्ति कमान के सेना कमाण्डर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास भी उपस्थित रहे।

शर्मा ने कहा कि जनभागीदारी ही किसी भी राष्ट्रीय उत्सव की असली शक्ति होती है। आर्मी डे परेड को आम लोगों ने अपने स्नेह और उत्साह से सफल बनाया। उन्होंने इस परेड की सफलता को विभिन्न विभागों के समन्वय का परिणाम बताया। उन्होंने भारतीय सेना के सभी सैनिकों और अधिकारियों का अभिनंदन किया और कहा कि सेना का अनुशासन व समर्पण राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है तथा उनके कठिन परिश्रम ने इस परेड को उत्कृष्ट बनाया।

शर्मा ने सेना दिवस परेड-2026 की संकलन पुस्तक एवं लघु फिल्म का विमोचन किया। इस दौरान कार्यक्रम में लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।

इस अवसर पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, सप्तशक्ति कमान के सेना कमाण्डर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, विभिन्न विभागों के अधिकारी सहित, सेना के अधिकारी भी उपस्थित थे।

ईरान ने बहरीन, कतर व यूएई पर हमले तेज किए

तेहरान/तेल अवीव, 06 मार्च। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष ने पश्चिम एशिया के अधिकांश इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। ईरान खाड़ी के देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और उससे संबंधित इलाकों को लगातार निशाना बना रहा है। गुरुवार देर रात बहरीन की राजधानी मनामा में फाइनेंशियल हार्बर टावर्स को निशाना बनाया गया। वहीं बहरीन, कतर, सऊदी अरब और जॉर्डन में एयर डिफेंस सिस्टम लगातार उसके हमलों को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। मौजूदा हालात के मद्देनजर कई देशों ने सुरक्षा अलर्ट जारी कर लोगों से घरों में रहने की अपील की है।

- **अमेरिका और इज़राइल के संयुक्त हमले के बाद ईरान ने बदले की कार्यवाही में कई पड़ौसी देशों को निशाना बनाया**

सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि सेंट्रल अल-खारज गवर्नरेट के पूर्व में एक क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया। बाद में मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी कि रियाद क्षेत्र के पूर्व में तीन ड्रोन को भी मार गिराया गया।

उधर कतर के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसकी एयर डिफेंस फोर्स ने दोहा स्थित अल उदीद एयर बेस को निशाना बनाकर किए गए एक ड्रोन हमले को विफल कर दिया। यह एयर बेस अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना माना जाता है। दोहा में सुबह करीब 4 बजे धमाकों की जोरदार आवाजें सुनीं गयीं, जो ईरान से आए ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के दौरान हुई थीं। पिछले पांच दिनों में सैन्य बेस को निशाना बनाकर दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई।

सुखोई-30 फाइटर जैट क्रैश, दोनों पायलट की मौत

वायु सेना की टीम को हादसा स्थल तक पहुंचने में चार घंटे का समय लगा

कार्बी आंगलोंग (असम), 06 मार्च। असम के कार्बी आंगलोंग जिले के पहाड़ी इलाके में गुरुवार देर शाम को सुखोई-30 एमकेआई फाइटर एयरक्राफ्ट के क्रैश होने से दोनों पायलटों की मौत हो गई।

दोनों की पहचान स्क्वाड्रन लीडर अनुज और को-पायलट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुरागकर के रूप में हुई है। लेफ्टिनेंट पूर्वेश भारतीय वायु सेना में फ्लाइंग नेविगेटर थे। हादसे की आधिकारिक जानकारी आईएएफ ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए दी है। दुर्घटना स्थल से दोनों वायु सैन्य कर्मियों के शव मिल गए हैं।

भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की एक्स पोस्ट में भारतीय वायु सेना ने स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पुर्वेश दुरागकर के निधन की जानकारी दी गई है। कहा गया है कि दोनों को सुखोई-30 दुर्घटना में घातक चोटें आईं।

- **जोरहट से टेकऑफ करने के कुछ देर बाद ही प्लेन कार्बी आंगलोंग जिले के दुर्गम पहाड़ी इलाके में क्रैश हो गया।**

हादसा गुरुवार रात लगभग 7 बजे के आसपास हुआ। विमान से संपर्क टूटने के बाद जोरहाट वायुसेना की टीम ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। हादसास्थल पर वायु सेना की टीम को पहुंचने में लगभग चार घंटे का समय लगा। हालांकि, हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है।

बताया गया है कि जोरहाट से टेक-ऑफ करने के कुछ ही देर बाद प्लेन कार्बी आंगलोंग जिले के दुर्गम पहाड़ी इलाके में क्रैश हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने तुरंत सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।

सूत्रों ने बताया कि एयरक्राफ्ट सुखोई-30 एमकेआई फाइटर जेट था, जिसने शाम को जोरहाट से उड़ान भरी थी। क्रैश साइट इनसानी आबादी से दूर एक जंगली और पहाड़ी इलाके में है, जिससे वहां के लोगों के लिए तुरंत पहुंचना मुश्किल था।

राजनाथ सिंह व राहुल गांधी ने लड़ाकू विमान हादसे के पायलटों को श्रद्धांजलि दी

नई दिल्ली, 06 मार्च। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने असम के कार्बी आंगलोंग जिले में हुए लड़ाकू विमान हादसे में वायु सेना के दो पायलटों की शहादत पर दुख व्यक्त किया।

राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि सुखोई-30 विमान हादसे में दोनों पायलटों स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुर्गाकर के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। देश के लिए उनकी हिम्मत और सेवा को हमेशा गर्व और आभार के साथ याद किया जाएगा। दुखी परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। दुख की इस घड़ी में देश उनके साथ मजबूती से खड़ा है।

- **रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों पायलटों को उनकी हिम्मत और सेवा के लिए हमेशा आभार व गर्व के साथ याद किया जायेगा।**

राहुल गांधी ने अपनी शोक संवेदना में कहा कि भारतीय वायुसेना के वीर जवान स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश का विमान दुर्घटना में शहीद होने का समाचार अत्यंत दु:खद और पीड़ादायक है। इन वीर सपूतों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि असम में हुई विमान दुर्घटना में दोनों वीर जवानों की शहादत का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक-संतप्त परिवारों को इस कठिन समय में संबल प्रदान करने की कामना की।

'मैं कांग्रेस का राज्यसभा का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

घर की छत पर इसी पार्टी का झंडा फहराया करता था।

बाद में वे कांग्रेस में शामिल हुए और फिर के. राजू, एक पूर्व आईएएस अधिकारी से मिले, जो सभी उभरते हुए दलितों के गॉडफादर हैं और राहुल गांधी के चारों ओर दलितों की एक दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, "दलितों के लिए, दलितों द्वारा, दलितों के साथ।"

के. राजू ने उन्हें राहुल गांधी से मिलवाया और उन्हें राज्यसभा भेजने के लिए मनाया।

राहुल गांधी ने हरियाणा के किसी वरिष्ठ नेता से सलाह किए बिना ही अपनी सहमति दे दी।

करमवीर बौद ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फोन किया और उन्हें सूचित किया कि "मैं करमवीर बौद हूं और मैं राज्यसभा का उम्मीदवार हूं, कल नामांकन दाखिल करने के लिए आइए।" हुड्डा जी हैरान रह गए और सामान्य होने में समय लिया।

इसी तरह रणदीप सिंह सुरजेवाला, शैलजा और हरियाणा के अन्य पार्टी नेताओं के साथ भी हुआ।

नेता असमंजस में रहे, विधायक नहीं जानते थे कि वे कौन हैं, लेकिन राहुल गांधी खुश हैं कि उन्हें एक दलित मिल गया जो उनके एजेंडा के अनुरूप है।

इस एजेंडा के प्रति वे बेहद जूनूनी हैं और किसी भी कीमत पर इसे लागू करना चाहते हैं।

के. राजू वे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस में दलितों के नरेटिव को नियंत्रित करना चाहते हैं। वे पार्टी में स्थापित दलित नेताओं, जैसे उदय भान और अशोक तंवर को प्रोत्साहित नहीं करना चाहते। वे एक नए व्यक्ति को चाहते थे, जिसे वह नियंत्रित कर सकें।

- **हरियाणा में राज्यसभा चुनाव का नतीजा इस सवाल का जवाब ढूंढने में शायद कुछ मदद करेगा।**

ठीक है यह भी, लेकिन क्या राहुल गांधी कोई विचार नहीं करते, या क्या उनका विश्वास इतना अंधा है कि वे हर निर्णय को के.सी. वेणुगोपाल, के. राजू या "जय जगत" जैसों को सौंपते रहते हैं?

जय जगत अपनी ताकत दिखा रहा है और यह संकेत देना चाहता है कि वह पार्टी में निर्णयों को नियंत्रित कर रहा है और वह बॉस है क्योंकि बॉस उसके साथ है।

जय जगत ने तमिलनाडु की राज्यसभा सीट भी हासिल कर ली है, जो एक ईसाई दलित को मिली है, जो जय जगत से है और के. राजू द्वारा समर्थित है।

भाजपा ने कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार को हराने के लिए एक स्वतंत्र उम्मीदवार खड़ा किया है, जो बुनियादी तौर पर भाजपा से है, उसके पास ढेर सारा पैसा है और वह कांग्रेस के विधायकों को खरीदने के लिए तैयार है।

क्या राहुल गांधी जीवन से कोई सबक नहीं सीखते? या क्या वे बस इस कारण से परवाह नहीं करते, क्योंकि वे इतने विशेषाधिकार प्राप्त हैं? हरियाणा का घटनाक्रम रोमांचक रहेगा, क्योंकि यहां पैसे, सत्ता, निराशा और गुस्से का खेल होगा।

अमेरिका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

खेड़ा ने कहा कि जब रूस भारत को तेल देने के लिए तैयार था, तब मोदी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन अमेरिका की अनुमति मिलने के बाद ही सरकार सक्रिय हुई। अमेरिका ने भारत को छूट दी है, जबकि छूट वहीं दी जाती है , जहां प्रतिबंध लागू होते हैं।

कोटा का डॉक्टर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सिविल सेवा के लिए चयनित किया गया था, जहां वे वर्तमान में प्रशिक्षण ले रहे हैं।

स्व-अनुशासन और दृढ़ता में विश्वास रखने वाले अनुज ने अपनी तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग पर भरोसा किया और दिल्ली के "एंश्योर" आईएएस से इंटरव्यू गाइडेंस प्राप्त की।

साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले अनुज के पिता कोटा में न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करते हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी हैं।

कुल 958 उम्मीदवारों ने आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और अन्य सेवाओं के लिए क्वालीफाई किया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइटों पर रोल नंबर के आधार पर परिणाम देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं।

यूपीएससी ने एक बयान में कहा, "अंक, परिणाम की घोषणा के 15 दिनों के भीतर वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।"

लिखित सीएसई परीक्षा अगस्त 2025 में आयोजित की गई थी, जबकि व्यक्तित्व परीक्षण (पर्सनैलिटी टेस्ट) दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच हुआ था।

अनुज के अलावा प्रदेश के दस अन्य अभ्यार्थियों का भी चयन हुआ है। ये हैं, बहरोड़ के तरुण यादव (49 वीं रैंक), बालोतरा के गौरव चोपड़ा (83 वीं रैंक), बूंदी के सौरभ शर्मा (146 वीं रैंक), तिजारा के निशांत यादव (237 वीं रैंक), बालोतरा के जितेन्द्र प्रजापति (287 वीं रैंक), पोकरण के प्रवीण दान रत्नू (499 वीं रैक), सीकर के संजय कुमार (502 वीं रैक), जयपुर के संभव पाटनी (608 वीं रैंक), तिजारा के बादल यादव (665 वीं रैंक), दौसा के आशीष शर्मा (722 वीं रैक)।

'अमेरिका ने दया की, भारत को रुस से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

साद अल काबी ने यह भी कहा कि अगर संघर्ष तुरंत समाप्त हो भी जाता है तो कतर को अपनी सामान्य आपूर्ति व्यवस्था को बहाल करने में "हफ्तों से महीनों" तक का समय लगेगा।

भारत में सभी तेल रिफाइनरियों से कहा गया है कि वे "यह सुनिश्चित करें कि उनके पास उपलब्ध प्रोपेन और ब्यूटेन का उपयोग रसोई गैस उत्पादन के लिए किया जाए।" सामान्यत: भारत की अधिकांश एलपीजी मध्य पूर्व से ही आती है, जो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है।

भारत ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भागदौड़ कर रहा है, क्योंकि होर्मुज़ जलसंधि के माध्यम से टैंकर ट्रैफिक ठप हो गया है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल शिपिंग मार्गों में से एक है।

यूएस ट्रेज़री सचिव ने कहा कि वह भारतीय रिफाइनरियों को पहले से समुद्र में मौजूद रूसी माल खरीदने के लिए एक शॉर्ट-टर्म छूट देगा। ट्रैज़री सचिव स्कॉर्ट बेसैंट ने कहा, "वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए, ट्रेजरी विभाग भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए अस्थायी तौर पर 30 दिन की छूट दे रहा है।"

"उन्होंने कहा जानबूझकर यह शॉर्ट-टर्म छूट दी गई है क्योंकि इससे रूस को कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि यह केवल समुद्र में पहले से फंसे हुए तेल की खरीद फरोख्त की अनुमति देता है।

बेसेंट ने इस छूट को एक अस्थायी उपाय के रूप में वर्णित किया, जबकि वॉशिंगटन भारत को अधिक अमेरिकी कच्चा तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है।

उन्होंने "यह अस्थायी उपाय ईरान द्वारा वैश्विक ऊर्जा को बंधक बनाने के प्रयास के कारण उत्पन्न दबाव को कम करेगा," उन्होंने कहा।

गल्फ क्षेत्र में यूएस-इज़राइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के आर्थिक प्रभाव को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है।

होर्मुज़ जलसंधि मार्ग भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत कच्चे तेल और एलएनजी दोनों के लिए खाड़ी उत्पादकों पर भारी निर्भर है।

भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 85 प्रतिशत और एलएनजी की जरूरत का 45 से 50 प्रतिशत आयात करता है। भारत के तेल आयात का लगभग 40 प्रतिशत सामान्यत: होर्मुज़ से गुजरता है, जहां टैंकर ट्रैफिक अब ठप हो चुका है।

चूंकि भारत द्वारा खरीदी जा रही कच्चे तेल की शिपमेंट पहले से ही बाजार में मौजूद हैं, दिल्ली को मौजूदा कीमतों पर भुगतान करना होगा, बजाय इसके कि वह रूस से पहले की तरह रियायती दरों पर सौदा कर सके।

यह भारत के लिए बुरी खबर है क्योंकि तेल अब 2022 के बाद अपनी सबसे बड़ी साप्ताहिक वृद्धि की ओर बढ़ रहा है, व्यापारियों के अनुसार। गोल्डमैन साक्स ने चेतावनी दी है कि कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर जा सकती हैं, जबकि जेपी मॉर्गन ने कहा है कि कीमत 120 तक पहुंच सकती है।

भारत पहले ही रूसी कच्चे तेल के दो शिपमेंट्स को खरीद चुका है, जो पास के समुद्र में चल रहे थे।

प्रत्येक टैंकर में लगभग 700,000 बैरल तेल है। एक तीसरा रूसी टैंकर भी अपना रास्ता बदल चुका है और माना जाता है कि वह भारतीय बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है।

रॉयटर्स के अनुसार, कुल मिलाकर, लगभग 9.5 मिलियन बैरल रूसी कच्चा तेल वर्तमान में भारत के पास स्थित जहाजों पर है।

वैश्विक स्तर पर, समुद्र में फंसे हुए रूसी तेल की मात्रा कहीं अधिक है। व्यापार खुफिया कंपनी केपलर के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 130 मिलियन बैरल रूसी कच्चा तेल टैंकरों पर मौजूद है। चीनी खरीदारों से प्रतिस्पर्धा, जो उसी तेल के लिए बोली लगा रहे हैं, भारत के लिए एक और चुनौती प्रस्तुत करता है।

इस बीच, घरेलू ईंधन आपूर्ति की सुरक्षा के लिए, भारत ने तेल रिफाइनरियों से एलपीजी का उत्पादन अधिकतम करने और इसे तीन राज्य-स्वामित्व वाली ईंधन खुदरा कंपनियों: इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम को आपूर्ति करने का आदेश दिया है।

अधिकारियों ने यह भी रिफाइनरियों से प्रोपेन और ब्यूटेन को पेट्रोकेमिकल उत्पादन में भेजने से रोकने के लिए कहा है, जिससे उन्हें औद्योगिक उत्पादन के मुकाबले एलपीजी को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर किया गया है। तीन कंपनियों को केवल घरेलू ग्राहकों को ईंधन बेचने का निर्देश दिया गया है।

राज्य-स्वामित्व वाली कंपनियां, जिनमें इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और मंगलेश्वर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स शामिल हैं, भी व्यापारियों के साथ रूसी माल की त्वरित डिलीवरी प्राप्त करने के लिए बातचीत कर रही हैं। भारतीय राज्य रिफाइनरियों ने अब तक व्यापारियों से लगभग 20 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदा है।

क्या ट्रम्प ईरान युद्ध ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

थे। यह एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर थी, जो पराजित महसूस कर रहा हो और जिसे मानो किसी दूसरी दुनिया से मदद की जरूरत हो।

वैसे भी ट्रंप अब कुछ भ्रमित से दिखाई दे रहे हैं और ऐसे दावे कर रहे हैं, जिन्हें शायद मौजूदा तथ्यों से साबित करना मुश्किल है। उन्हें यह कहते सुना गया है कि ईरान के अगले नेता के चयन में उनकी व्यक्तिगत भूमिका बिल्कुल जरूरी है। इसी के साथ, वे दुनिया भर में मौजूद ईरानी राजनयिकों से शरण लेने और एक नया ईरान बनाने के लिए कहीं और से मदद लेने की अपील कर रहे हैं।

इसी सांस में उन्होंने ईरानी सेना और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आई. आर. जी. सी.) सदस्यों को चेतावनी भी दी है कि वे हथियार डाल दें, क्योंकि उनके पास दूसरा विकल्प केवल मौत है। शुरुआत में ईरान के खिलाफ कुछ बढ़त हासिल करने के बाद अब अमेरिका को अपने हमले के कारण कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। अरब देशों में अमेरिका के सहयोगियों के खिलाफ ईरान के क्षेत्रीय तेल केंद्रों को लगभग ठप कर दिया है। इलाके की बड़ी तेल कंपनियां अपने उत्पादन संयंत्र बंद कर रही हैं और तेल की आपूर्ति बहुत कम हो गई है। स्टेट ऑफ होरमुज़ से नियमित जहाजों की आवाजाही भी रुक गई है और तेल का परिवहन लगभग ठहर गया है।

दुनिया भर के बड़े बाजारों में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। शुक्रवार को तेल का अंतरराष्ट्रीय मानक मूल्य 91 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया, जो हमले से पहले के दिनों की तुलना में काफी अधिक है। बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इससे प्रभावित होने की आशंका जता रही हैं और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पैक्ट्स कमज़ोर पड़ते दिख रहे हैं।

- **अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में ऑयल की कीमत 91 डॉलर प्रति बैरल पार कर रही है तथा अमेरिका में भी, बाजार में मंहगाई व दाम बढ़ रहे हैं। जो अमेरिका की जनता की सोच का मानक माना जाता है और इससे ट्रंप की लोकप्रियता निःसंदेह गिरेगी, और ट्रंप के लिए यह चिन्ता का विषय है।**
- **साथ ही नाटो देश अब ट्रंप को समर्थन देने के मुद्दे पर बिखरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है, ट्रंप अब ईरान की लड़ाई में अकेले खड़े हैं, युद्ध भूमि में।**

अमेरिका को भी इसके आर्थिक असर का सामना करना पड़ रहा है। ताजा रोजगार आंकड़े बताते हैं कि नौकरियों के सृजन में कमी आई है, जबकि कुछ समय पहले तक इनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। कीमतें भी धीरे-धीरे बढ़ रही हैं, जो जनता के मूड को प्रभावित करने वाला संकेत है। अमेरिकी लोग महंगाई से नाराज रहते हैं और इसका असर राष्ट्रपति की लोकप्रियता पर जरूर पड़ेगा, जो वैसे भी लगातार गिर रही है।

दूसरी ओर, यूरोप में भी अमेरिका के नाटो सहयोगियों ने ट्रंप के सामने अलग रुख अपना लिया है। पहले ट्रंप ने कहा था कि अगर किसी नाटो सदस्य पर हमला हुआ तो वे रक्षा की जिम्मेदारी से पीछे हट सकते हैं। लेकिन अब स्थिति उलट गई है और ट्रंप को ही अपने सहयोगियों से मदद मांगनी पड़ रही है।

हालांकि स्पेन ने साफ मना कर दिया है कि अमेरिका उसके किसी भी सैन्य अड्डे का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यू. के. ने केवल सीमित उपयोग की अनुमति दी है। फ्रांस ने राष्ट्रपति से कहा है कि वे ईरान के साथ तुरंत युद्धविराम के लिए बातचीत शुरू करें। वहीं जर्मनी ने अब तक अपना स्पष्ट रुख नहीं बताया है। ऐसा लगता है कि ईरान के साथ इस टकराव में ट्रंप लगभग अकेले खड़े रह गए हैं।

प्रधानमंत्री ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बढ़ाया जो इस बार अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षण कठिन हो सकते हैं, लेकिन यह यात्रा का केवल एक पड़ाव है और आगे अनेक अवसर उपलब्ध हैं।

बिहार में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चुनाव करे। इस संदर्भ में सीमा गुप्ता का नाम उछाला जा रहा है, जो संघ पृष्ठभूमि से बताई जाती हैं।

नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने के लिए ताकत जुटाने के बाद, यह निश्चित माना जा रहा है कि भाजपा अपने उम्मीदवार को मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करेगी। हालांकि, यह भी संभव है कि कुमार के बेटे को सत्ता की राजनीति में लाया जाये और नई सरकार में उपमुख्यमंत्री बनाया जाए।

राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में एक नया और अप्रत्याशित चेहरा चुनकर भाजपा यह राजनीतिक संदेश दे सकती है कि बिहार में पूरी तरह से नयी शुरुआत की जा रही है। इन परिदृश्यों में नई सरकार को भाजपा नेतृत्व का प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्राप्त भी माना जाएगा। वहीं, ऐसी सम्भावना नहीं है कि नेतृत्व जेडीयू को विभाजित करने की कोशिशों में लगेगी। हालांकि नीतीश कुमार जैसे किसी प्रभावशाली नेता के बिना पार्टी के पास लंबी अवधि तक अस्तित्व में रह पाना मुश्किल होगा। कुमार अब भी ईबीसी वर्ग में लोकप्रिय हैं और पिछले वर्षों में उन्होंने महिला वोटरों में एक मजबूत समर्थन आधार बनाया है। भाजपा इन वर्गों का समर्थन खोना नहीं चाहेगी। इसलिए, यह संभावना है कि भाजपा नेतृत्व कुमार के साथ सदाशयतापूर्ण और सुलझे हुये तरीके से ही पेश आएगा। इसके साथ ही, यह भी संभावना है कि समाजवादी पृष्ठभूमि के चलते बिहार में हिंदुत्व के कट्टर संस्करण को फिलहाल नहीं उतारा जाएगा।

अमेरिका के खिलाफ असंतोष ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अड़ा रहा और उसने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष नाटो की सामूहिक रक्षा प्रतिबद्धताओं के दायरे में नहीं आता।

इस मतभेद का मूल कारण यह है कि नाटो की सदस्यता का मतलब यह नहीं है कि किसी सदस्य देश को हर उस युद्ध में शामिल होना पड़े, जिसमें कोई दूसरा सदस्य शामिल हो। नाटो की अनुच्छेद-5 वाली सामूहिक रक्षा धारा तभी लागू होती है, जब किसी सदस्य देश पर हमला हो। मौजूदा संघर्ष में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को नाटो क्षेत्र पर हमला नहीं माना जा रहा है। इसलिए स्पेन पर इसमें भाग लेने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। मैड्रिड ने अपने रुख को नाटो के खिलाफ चुनौती नहीं, बल्कि उसके वास्तविक समझौते का पालन बताया है।

स्पेन का यह रुख उसके इतिहास और, विशेष रूप से, इराक युद्ध के अनुभव से भी जुड़ा है। सन् 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री होज़े मारिया अज़नार की कंज़रवेटिव सरकार ने अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर हमले का समर्थन किया था और वॉशिंगटन तथा लंदन के साथ खड़ी हुई थी। इस फैसले के खिलाफ पूरे स्पेन में भारी विरोध प्रदर्शन हुए और यह देश के वर्तमान इतिहास की विदेश नीति के सबसे विवादित फैसलों में से एक बन गया। सन् 2004 की मैड्रिड ट्रेन बॉंबिंग्स के बाद यह विरोध और तेज हो गया, जिसमें करीब 200 लोग मारे गए थे और जिसने पूरे स्पेन को झकझोर दिया था। इसके बाद जब समाजवादी नेता होज़े लुइस रॉड्रिगेज़ ज़ापाटेरो की सरकार सत्ता में आई तो उसने इराक से स्पेनिश सैनिकों को वापस बुला लिया। तब से स्पेन की सरकारें, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की हों, मध्य-पूर्व में अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य अभियानों में शामिल होने को लेकर बेहद सावधान रही हैं।

यह ऐतिहासिक अनुभव प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज़ की मौजूदा नीति में भी साफ दिखाई देता है। उनकी सरकार बार-बार कह चुकी है कि इराक जैसी गलतियों को दोहराया नहीं जाना चाहिए। स्पेन के अधिकारियों का कहना है कि मध्य-पूर्व में एकतरफा सैन्य कार्रवाई से अक्सर शांति के बजाय अस्थिरता पैदा हुई है, जबकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को कूटनीति और तनाव कम करने पर ध्यान देना चाहिए।

मैड्रिड और वॉशिंगटन के बीच टकराव में आइडियोलॉजी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सांचेज़ एक सैंट्रल -लैफ्ट सोशलिस्ट सरकार का नेतृत्व करते हैं, जो बहुपक्षीय सहयोग, अंतरराष्ट्रीय कानून और कूटनीति पर जोर देती है। इसके विपरीत ट्रंप की विदेश नीति अधिक आक्रामक और एकतरफा रही है। इसलिए ईरान को लेकर यह टकराव केवल रणनीति का मतभेद नहीं, बल्कि दोनों सरकारों की सोच में व्यापक अंतर को भी दिखाता है। तनाव का एक और अंदरुनी कारण नाटो के भीतर रक्षा खर्च को लेकर चल रहा पुराना विवाद है। ट्रंप बार-बार यूरोपीय सहयोगियों की आलोचना करते रहे हैं कि वे रक्षा पर पर्याप्त खर्च नहीं करते और उन्होंने उनसे सैन्य बजट बढ़ाने की मांग की है। स्पेन अपनी आर्थिक क्षमता की तुलना में नाटो के सबसे कम रक्षा खर्च करने वाले देशों में रहा है और उसने खर्च में बहुत बड़ी बढ़ोतरी करने के दबाव का विरोध किया है। इसलिए ईरान युद्ध को लेकर यह विवाद पहले से मौजूद मतभेदों की पृष्ठभूमि में सामने आया है।

स्पेन का रुख यूरोप में बढ़ती उस बहस को भी दर्शाता है, जिसमें "रणनीतिक स्वायत्तता" (स्ट्रैटेजिक ऑटोनोमी) की बात की जा रही है। कई यूरोपीय सरकारों का मानना है कि यूरोपियन यूनियन को यू.एस. मिलिट्री पहलों के साथ स्वत: जुड़ने के बजाय अपनी इंडिपैंडेंट सिक्यूरिटी और फॉरेन पॉलिसी डवलप करनी चाहिए। स्पेन उन देशों में से रहा है, जो ग्लोबल डिप्लोमेसी और झगड़े सुलझाने में यूरोप की मजबूत भूमिका की वकालत करते रहे हैं। ईरान के खिलाफ युद्ध से दूरी बनाकर मैड्रिड यह संकेत दे रहा है कि अंतरराष्ट्रीय संकटों में यूरोपीय सहयोगी हमेशा वॉशिंगटन का अनुसरण नहीं करेंगे। घरेलू राजनीति भी इसमें एक अहम कारक है। स्पेन में जनमत विदेशी सैन्य हस्तक्षेपों, खासकर मध्य-पूर्व में, को लेकर काफी संदेहपूर्ण है। मैड्रिड की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार में ऐसे राजनीतिक दल भी शामिल हैं जो युद्ध के कड़े विरोधी हैं और अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान कूटनीति से करने के पक्ष में हैं। इसलिए ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान का समर्थन करना सांचेज़ सरकार के लिए राजनीतिक रूप से जोखिम भरा हो सकता है।

रणनीतिक गणनाओं ने भी स्पेन की प्रतिक्रिया को प्रभावित किया है। मैड्रिड को डर है कि ईरान के साथ लंबा युद्ध पूरे मध्य-पूर्व को अस्थिर कर सकता है, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बाधित कर सकता है और यूरोप की ओर नई प्रवासन लहर पैदा कर सकता है। इसलिए स्पेन के नीति-निर्माता तनाव कम करने को न केवल वैश्विक स्थिरता, बल्कि यूरोप की अपनी सुरक्षा के लिए भी जरूरी मानते हैं।

परिणाम यह है कि स्पेन कह रहा है कि अलायंस मेम्बरशिप का मतलब यह नहीं है कि वह हर अमेरिकी सैन्य अभियान में अपने-आप शामिल होगा। युद्ध में शामिल होने से इनकार करके मैड्रिड ने पश्चिमी गठबंधन के भीतर हो रहे व्यापक बदलाव को उजागर किया है, जहां नैशनल पोलिटिकल सोच और रीजनल स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज़ तेजी से यह तय करती हैं कि नाटो के अलग-अलग मेम्बर ग्लोबल झगड़ों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं।

जो विवाद शुरुआत में केवल सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल को लेकर था, वह अब एक बड़े सवाल में बदल गया है, गठबंधन की एकजुटता की असली प्रकृति क्या है, अमेरिकी नेतृत्व की सीमाएं क्या हैं, और क्या यूरोप के कुछ देश अब अपनी अधिक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना चाहते हैं।